9/26/24, 2:51 PM

Bering Seraghat - Pithoragarh

(-1)

आदेश.

राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–1887 / XVIII (II) / 2015–18(169) / 2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.–सा.नि.) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–111 / XXVIII(7)50(39)–15 / 2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील बंगापानी अन्तर्गत सेराघाट से बोना मोटर मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम फर्केकोट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–09 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 57 रकवा 0.100 है0,386 रकवा 0.360 है0, 388 रकवा 0.240 है0, 390 रकवा 0.120 है0, 474 रकवा 0.085 है0, 475 रकवा 0.010 है0, 477 रकवा 0.210 है0, 478 रकवा 0.060 है0, 480 रकवा 0.075 कुल 09 खेतों की 1.260 है0 तथा ग्राम मोल्फा के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–34 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 7399 रकवा 1.400 है0, 7567 रकवा 0.060 है0, 7569 रकवा 0.050 है0, 7571 रकवा 0.510 है0, 7584 रकवा 0.320 है0, 7586 रकवा 0.280 है0, 7588 रकवा 0.800 है0 कुल 07 खेतों की 3.420 है0 इस प्रकार उक्त दो ग्रामों के कुल 16 खेतों की 4.680 है0 राज्य भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260 / वित्त अनुभाग–3 / 2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा लोक निर्माण अनुभाग–2 के प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जे.ड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132 / 2011(एस.एल.पी.) / सी संख्या–3109 / 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436 / 2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक सितम्बर 07, 2015

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-1709 / सात-97 / 2014-15 दिनांक सितम्बर 08 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग डीडीहाट।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
4. तहसीलदार बंगापानी को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खसरा की प्रति संलग्न कर प्रेषित जा रही है।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।